खुलासा : इंडिया टीवी और दैनिक जागरण वाले पैसा लेकर भाजपा के लिए दंगा फैलाने वाली खबरें करते हैं प्रसारित

कासगंज में दैनिक जागरण ने निभाई दंगाई अखबार की भूमिका

जनज्वार, दिल्ली। कई बड़े खुलासों के लिए चर्चित रही वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने फिर एक नया खुलासा कर सनसनी फैला दी है। इससे पहले काले धन के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों के यह वेबसाइट खुलासे कर चुकी है।

इस बार कोबरा पोस्ट ने 'ऑपरेशन 136' नाम के अपने स्टिंग में इस बात का पर्दाफाश किया है कि किस तरह देश के बड़े—बड़े मीडिया समूह पैसे लेकर खबरें चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और देश के सबसे ज्यादा नाजुक सांप्रदायिकता जैसे मसलों पर ये हिंदुत्व एजेंटों के आगे बिकते नजर आते हैं। कोबरा पोस्ट के खुलासे के मुताबिक सो कॉल्ड जाने माने मीडिया हाउसेस इसके लिए काला धन तक स्वीकारते हैं।

आज दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया कि मीडिया समूह 'हिन्दुत्व' के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पैसे लेकर राजनीतिक अभियान चला रहे हैं।

अपने खुलासे में कोबरा पोस्ट ने कई न्यूज चैनलों, अखबार, वेबसाइटों के उच्च प्रबंधन से बातचीत के वीडियो साझा किए हैं, जो पैसे के बदले किसी भी तरह की खबरें चलाने को तैयार थे।

जिन मीडिया समूहों का कोबरा पोस्ट ने नाम लिया, उनमें हिंदी न्यूज चैनल इंडिया टीवी, साधना प्राइम, हिन्दी खबर, हिन्दी अखबार दैनिक जागरण, नामी वेबसाइट स्कूप हूप समेत सब टीवी, अमर उजाला, डीएनए, यूएनआई, समाचार प्लस, 9एक्स, पंजाब केसरी, rediff.com भी शामिल हैं। स्टिंग में ये मीडिया मालिकान—प्रबंधक पैसे के बदले किसी भी तरह यानी दंगे फैलाने वाली खबरें चलवाने को तैयार नजर आए।

कोबरा पोस्ट के मुताबिक इस स्टिंग ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन 136 इसलिए रखा, क्योंकि कुछ समय पहले आई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है।

नेताओं के अंगने की नचनिया बन गया है मीडिया

स्वराज अभियान के प्रमुख नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन 136 पर ट्वीट किया है, कोबरा पोस्ट द्वारा प्रेस क्लब में मुख्यधारा के कई मीडिया हाउसों का पर्दाफाश किया जा रहा है, उसने ऑपरेशन 136 के नाम से खौफनाक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें मीडिया की पोल खुलकर रह गई। प्रमुख मीडिया संगठनों के मालिकों और प्रबंधकों ने पैसे के बदले सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और अपमानजनक प्रचार वाली खबरों को खुशी—खुशी खासतौर पर कवरेज दिया और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए मीडिया मालिकों—प्रबंधकों को पैसे का भुगतान किया हिंदुत्व एजेंटों ने।

खुलासा : काला धंधा गोरे लोग.....भाजपा सरकारों ने कोयला अदानी के पास गिरवी रखा

(म. मो. विशेष) लीजिए एक और घोटाला सामने आया है और वह घोटाला भी छोटा मोटा नही है पूरे 125 करोड़ का घोटाला है। छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों बेच दिया गया है। ढाई हजार मिलियन टन क्षमता वाले छह कोल ब्लॉक को नीलाम न करके तीन भाजपा शासित राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों को आवंटित कर दिया गया है।

कहने को कोल ब्लॉक्स कागजों में तो सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों के हैं, लेकिन उनकी असली संपत्ति एक निजी कंपनी अडानी को माइन डेवलप एंड ऑपरेट (एमडीओ) नियुक्त करके सौंप दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में कुल 88 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला निकालने का काम या तो अडानी के पास पहुंच चुका है या फिर इसकी तैयारी अंतिम चरणों में है।

उदाहरण के लिए आप देखिए कि पतुरिया गिधमुड़ी कोल ब्लॉक भैया थान पॉवर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया है। यह पॉवर प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार को बनाना था लेकिन यह परियोजना शुरु ही नहीं हो सकी और इंडिया बुल्स वापस चली गई। लेकिन इस कोल ब्लॉक से कोयला निकालने की तैयारी हो रही है। जब परियोजना ही नहीं है तो फिर कोयला क्यों निकाला जाएगा ? किसके लिए निकाला जाएगा ? छत्तीसगढ़ सरकार कोयला व्यापारी तो है नहीं तो फिर यह मोदीजी के इशारे पर अडानी को उपकृत करने के अलावा और क्या है ?

ओर इन्हीं आधार पर अडानी कह रहे हैं कि कि अगले दशक में उनका कोयला उत्पादन 150 मिलियन टन हो जाएगा।

जिन खदानों से जुड़े हुए कोल ब्लॉक में हिंडाल्को 3500 रु प्रति टन कोयला निकाल रही हैं वही अडानी को मात्र 100 रु प्रति टन में ठेका दिया गया है कहने को तो यह आरोप कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश पटेल लगा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र स्त्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है कि किस तरह से सरकारी अधिसूचनाओ में मनमाने परिवर्तन करा कर अडानी किस तरह से कोयले को खुले बाजार में बेच कर अरबो खरबो के मुनाफे का खेल खेलने को तैयार बैठे।

दिन रात 2 जी स्कैम ,राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोल ब्लॉक में भ्रष्टाचार आदि घोटाले की राग रागनियों को गा कर जो लोग सत्ता में आये थे वो ही आज नया कोयला घोटाला करने से बाज नही आ रहे।

स्टाफ़ की भारी कमी से जूझ रहा ज़िला प्रशासन

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िला प्रशासन चलाने के लिये पहले एक एसडीएम कार्यालय व एक तहसील कार्यालय होता था। जनता की सुविधा के नाम पर अब 3 एसडीएम कार्यालय (बल्लबगढ, फ़रीदाबाद व बडखल) बना दिये गये हैं। इसी तरह बल्लबगढ व फ़रीदाबाद तहसील के अलावा बड़खल तहसील, मोहना, गौछी, तिगांव व धौज उपतहसील बना दी गयी हैं। इतना ही नहीं गुड़गांव से अलग करके फ़रीदाबाद को मंडल का दर्जा देकर यहां एक मंडलायुक्त की भी नियुक्ति कर दी। यहां किसको मंडलायुक्त लगाया जाय यह निर्णय करने में खट्टर सरकार को करीब एक वर्ष लग गया। इसके दफ़्तर के लिये कोई जगह नहीं मिली तो नहर विभाग के रेस्ट हाउस को ही दफ़्तर बना दिया।

तीन एसडीएम कार्यालय तो खड़े कर दिये परन्तु गत 3-4 माह से इन कार्यालयों में बैठाने के लिये खट्टर को पूरे 3 अफ़सर नहीं मिल पा रहे हैं। बल्लबगढ के एसडीएम का काम वहां के नगर निगम के संयुक्त आयुक्त देख रहे हैं। करीब 2 माह तक फ़रीदाबाद एसडीएम की पोस्ट खाली रखने के बाद नगर निगम एनआईटी के संयुक्त आयुक्त को ही यहां का भी काम सौंप दिया। बड़खल के एसडीएम रीगन कुमार से विधायक सीमा त्रिखा नाराज हो गयी तो उन्हें यहां से हटाकर कैथल भेज दिया, परन्तु कोई तैनात नहीं किया गया। 'हूडा' के एस्टेट अफ़सर की पोस्ट गत 5 माह से खाली पड़ी है, लोगों की फ़ाइलों के ढेर लगे पड़े हैं। जाहिर है ऐसे में तंग आये लोग, किसी भी एस्टेट अफ़सर के तैनात होने पर मोटी रिश्वतें देकर अपने काम निकलवायेंगे।

उक्त अफ़सरों के अलावा दफ़्तरों में काम करने वाले अन्य स्टाफ़ की भी भारी कमी है। प्रत्येक एसडीएम कार्यालय में विभिन्न पदों पर जहां 8-8 बाबू होने चाहिये वहां कहीं 4 हैं तो कहीं 2 ही बैठा रखे हैं। यही हाल सभी तहसीलों व उप तहसीलों का है। उपायुक्त को पूरे ज़िले का प्रशासन चलाने के लिये जहां कुल 106 छोटे बड़े बाबुओं के पद सृजित करके दिये गये हैं वहां फ़रवरी माह तक 55 यानी आधे से अधिक पद रिक्त पड़े थे। मार्च माह में नये भर्ती होकर भी आये तो मात्र 19, यानी नई भर्ती के बावजूद 36 पद फ़िर भी रिक्त छोड़ दिये गये। अगली भर्ती जब कभी होगी तब तक तीसियों पद और रिक्त हो चुके होंगे। इसी तरह पलवल उपायुक्त कार्यालय में 18 तथा नूह में 20 पद खाली पड़े हैं।

मंडलायुक्त का दफ़्तर खोल कर आयुक्त तो यहां बैठा दिया परन्तु स्टाफ़ की कोई व्यवस्था करना सरकार जरूरी नहीं समझती। इस कार्यालय के लिये कुल 27 विभिन्न पद स्वीकृत हैं। इन में से 9 रिक्त हैं। जो 18 पद भरे भी हैं वे इधर-उधर (उपायुक्त, एसडीएम तहसील कार्यालय आदि) से पकड़ कर बैठा रखे हैं। जाहिर है जब स्टाफ़ पूरा नहीं होगा तो मौजूद स्टाफ़ को ही डबल-डबल काम करना पड़ेगा। एक-एक बाबू को दो-दो सीटों का काम सम्भालना पड़ता है। जाहिर है इसके लिये दफ़्तर टाइम के बाद भी अतिरिक्त ओवर टाइम लगाना पड़ता है। दूसरी ओर जिन लोगों के काम फ़ाइलों में अटके पड़े हैं वे काम जल्दी कराने के चक्कर में बाबुओं पर दबाव भी बनायेंगे और लालच भी देंगे। इससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलना स्वाभाविक है।

भर्तियां न कर के पदों को रिक्त रखने के पीछे सरकार की मंशा यही रहती है कि सरकारी खर्च घटाया जाय। लेकिन इस तरह की मामूली बचत सरकार एवं जनता को कितनी महंगी पड़ती है यह सरकार की समझ से बाहर की बात है। स्कूलों में खाली पड़े पदों से बच्चों की पढाई का नुक्सान, अस्पतालों में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ के न होने से ग़रीब व लाचार जनता असहनीय कष्टों को भोग कर मरने को मजबूर। सरकारी बसों में ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य स्टाफ़ के न होने से कमाई करने वाली बसें खड़ी रहती हैं और सवारियां वैकल्पिक साधनों के हाथों लुटती हैं। रेलवे में ढाई लाख पदों को खाली रख कर सरकार ने अपना खर्च तो जरूर घटा लिया परन्तु रेल दुर्घटनाओं से होने वाले जान-माल के नुक्सान की उसे कोई चिंता नहीं।

सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार देना अपना दायित्व नहीं समझती, बेशक ना समझे, लेकिन जो सेवायें जनता को उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार का है, उसे पूरा करने के लिये आवश्यक नियुक्तियां करे। इतने भर से यदि किसी की बेरोजगारी दूर हो जाय तो भी सरकार को परेशानी है?

जानिए, जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में जातिवाद और दारू पार्टियां क्यों ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) बार एसोएिशन (वकीलों की संगठन) के चुनाव पूरे हरियाणा के साथ-साथ यहां भी छह अप्रैल को हाने तय हुए है। इसे लेकर आजकल कचहरी में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। बार के प्रधान तथा महासचिव पद के लिए सबसे ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है।

चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडों में प्रमुख हथकंडा जातिवाद का है। जातीय समीकरण जिसे राजनीतिक भाषा में आजक सोशल इन्जीनियरिंग कहा जाने लगा है, एक बड़ा हाथकंडा है। कुछ जातियां मिलकर यानि गठबंधन करके एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करती हैं। उसके बाद शुरू होता है पार्टियों यानि खाने पीने का दौर। खाने-पीने में आजकल फल, मिठाई व दूध आदि से काम नहीं चलता, इसके लिये अन्य बहुत से कीमती खाद्य व पेय उपलब्ध बनाये जाते हैं। इस पर प्रत्येक उम्मीदवार कई कई लाख खर्च कर देता है।

सवाल उठना लाजमी है कि इन पदो में ऐसा क्या है कि वकील साहेबान इतना भारी भरकम खर्चा उठाने का रोग पालते हैं ? इसे एक दृष्टांत से समझना आसान होगा । पिछले दिनों सैशन जज की अध्यक्षता में विजिलेंस कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें बार के प्रधान और महासचिव के साथ बार काऊंसिल सदस्य ओपी शर्मा भी मौजूद थे। शर्मा जी ने मीटिंग के दौरान बार महासचिव से पूछा कि बार की आय-व्यय का क्या हिसाब है ? बताया गया कि एक लाख 25 हजार की आय व एक लाख 20 हज़ार का खर्चा है

शर्मा जी ने कहा कि यह सारा खर्चा तथा 2 लाख अलग से वे तुरंत बार प्रधान व महासचिव को देने को तेयार हैं। यकीन न हो तो एडवांस अभी सैशन जज साहब के पास जमा करा देते हैं। शर्त यह है, वे किसी कैंटीन वाले से, पार्किंग ठेकेदार से तथा कोर्ट परिसर में बैठे किसी भी दुकानदार से आगे कोई वसूली नहीं करेंगे। इसका कोई तर्क संगत जवाब देने की बजाय दोनों पदाधिकारी आंय-बांय-शांय करने लगे।

इसके अलावा बार पदाधिकारी होने के नाते ये लोग न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव डालने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके जरिये ये मुअकिलों को बेज़ा लाभ दिला कर अपना करोबार एवं आय को बढाते हैं।

ओपी शर्मा इसे स्पष्ट शब्दों में दलाली कहने में संकोच कहीं करते। वे तो यहां तक भी कहते हैं कि दलाली करने वाले वकीलों को ही आज की न्यायपालिका बेहतर एवं सुविधाजनक समझती है। दलाली करने वाले बार पदाधिकारी उनकी किसी भी बेजा हरकत एवं रिश्वतखोरी पर सवाल खड़े नहीं करते। इसलिये न्यायपालिका भी परोक्ष रूप से ऐसे ही पदाधिकारियों को चयनित कराने का प्रयास करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 30 मार्च तक भी बार की वोटर लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं की गयी है, और इसे हर रोज़ सुविधानुसार संशोधित किया जा रहा है।

पीएलए यानी पंजाबी लॉयर्स एसोसिएशन

पढे लिखे वकीलों की जमात में एक अनौपचारिक संगठन पीएलए के नाम से भी है। इस खेमे की ओर से अश्वनी त्रिखा प्रधान पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। त्रिखा जी, विधायक सीमा त्रिखा के पति हैं। राजनीतिक सत्ता में तो उनकी भागीदारी हो ही चुकी है, अब बार की सत्ता पर भी काबिज होने की धुन सवार है।

दौड़ में जहां स्थानीय पूर्व विधायक एवं मंत्री महेन्द्र प्रताप सिंह उनका खुला विरोध करने को आतुर हैं, वहीं स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल गूजर ऊपरी तौर पर यानी दिखावे मात्र का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। विदित है कि बार में गूजर वोट चुनाव का रूख बदलने में अहम भूमिका निभाते आये हैं। इन वोटों की एक खासियत यह भी बताई जाती है कि अन्तिम समय पर ये लोग निर्णायक फ़ैसला लेकर खंडित मतदान की बजाय एकतरफ़ा मतदान करते हैं। ऐसे में अकेले पीएलए यानी पंजाबी वोटों के सहारे त्रिखा की नैया पार लगना आसान नहीं। जातिवाद और दारू पार्टियों से पार हो जाय तो बात अलग है।

अब बता पाना मुश्किल है कि रामदेव के 'स्वदेशी' और अन्ना के 'लोकपाल' में अधिक हास्यास्पद कौन हुआ ?